54 एकड़ जमीन का मुआवजा वितरण

मोकामा में छह लेन के पुल निर्माण की प्रक्रिया शुरू

संवाददाता ▷ पटना

मोकामा में गंगा नदी पर छह लेन सड़क पुल के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 14 अक्तूबर को शिलान्यास किये जाने के लगभग 10 माह बाद पुल निर्माण की गति में तेजी आयी है. पुल निर्माण करनेवाली कोलकाता की कंपनी वेल स्पैन ने मोबिलाइजेशन का काम तेज कर दिया है. अगर काम की गति ठीक रही, तो ढाई से तीन साल में पुल निर्माण का काम पूरा हो जायेगा. गंगा नदी पर औंटा व सिमरिया के बीच वर्तमान राजेंद्र सेतु से 480 मीटर पूरब समानांतर पुल का निर्माण होना है. दक्षिण में हाथीदह जंक्शन से आरंभ होकर उत्तर में सिमरिया घाट के पास मिलनेवाले दो किलोमीटर के नये छह लेन पुल का निर्माण हाईब्रिड एनूटी मोड से होगा. एनूटी मोड से बनने वाला बिहार का पहला सड़क पुल प्रोजेक्ट होगा. औंटा व सिमरिया के बीच छह लेन पुल के साथ फोरलेन एप्रोच रोड लगभग नौ किलोमीटर बनेगा. पुल व एप्रोच रोड के निर्माण में 1161 करोड़ का खर्च अनुमानित है. मोकामा में छह लेन पुल का निर्माण पीएम द्वारा दिये गये पैकेज का हिस्सा है.

22 हेक्टेयर जमीन का मुआवजा वितरण: औंटा व सिमरिया के बीच गंगा नदी पर छह लेन पुल व फोर लेन एप्रोच रोड निर्माण के लिए लगभग 44. 11 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है. इसमें 22 हेक्टेयर (लगभग 54 एकड़) जमीन का मुआवजा वितरण हो गया है. लगभग साढ़े 14 हेक्टेयर सरकारी जमीन के हस्तांतरण की प्रक्रिया चल रही है. मरांची गांव में बकास भूमि को रैयती बताने के कारण कुछ मामलों का निष्पादन नहीं होने से रैयतों का मुआवजा भुगतान लंबित है. सरकारी भूमि के लगभग 15 एकड़ हस्तांतरण को लेकर प्रस्ताव राजस्व व भूमि सुधार विभाग को भेजा गया है.

क्या है योजना

एनएच 31 बख्तियारपुर, मोकामा, बेगूसराय होते हुए पूर्णिया तक निर्माणाधीन फोरलेन सड़क को गंगा नदी पर जोड़ने के लिए इस छह लेन पुल का निर्माण हो रहा है. प्रोजेक्ट के तहत दो आरओबी का निर्माण भी प्रस्तावित है. आठ कलवर्ट भी बनेंगे. गंगा नदी के दक्षिण में हाथीदह जंक्शन के सामने से उत्तरी छोर पर सिमरिया घाट बिंद टोली होते हुए राजेंद्र पुल रेलवे स्टेशन व बरौनी थर्मल पावर स्टेशन के बीच एनएच 31 में मिलाने की योजना है. एनएचएआई के आधिकारिक सूत्र ने बताया कि पुल निर्माण करनेवाली कंपनी ने काम शुरू किया है.

क्या है हाइब्रिड एनूटी मोड

हाइब्रिड एनूटी मोड में निर्माण कंपनी को काम शुरू करने पर सरकार से आर्थिक सहयोग मिलता है. सरकार समय-समय पर काम के दौरान कंपनी को राशि देती है, ताकि निर्माण के दौरान राशि के अभाव में काम पर असर नहीं पड़े.